भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2688
मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

कृषि का सौरीकरण (सोलराइजेशन) और विद्युत योजनाओं में महिलाओं का सशक्तिकरण

2688 श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए राजसहायता और कृषि परिसंपत्तियों के सौरीकरण सहित राष्ट्रीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेलों के सौरीकरण और एफपीओ की भागीदारी, और ऊर्जा की लागत में कमी, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी और सौर परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाले एफपीओ में नेतृत्व की भूमिकाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण सहित स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इटावा के बढ़पुरा खंड में ट्यूबवेलों के सौरीकरण हेतु महिला उद्यमियों को दी गई राजसहायता की उपयोगिता, सौर परिसंपत्तियों के प्रबंधन में ओबीसी महिलाओं के नेतृत्व वाले एफपीओ को दी गई प्राथमिकता और डीज़ल पर निर्भरता में कमी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) और पीएम कुसुम योजना, दोनों ही मांग-संचालित योजनाएं हैं, जिनमें महिला उद्यमियों के लिए सब्सिडी का कोई अलग प्रावधान नहीं है।

PMSG: MBY के अंतर्गत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 05.08.2026 की स्थिति के अनुसार, कुल 77,65,047 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 14,894.95 MW की कुल क्षमता के 41,94,051 रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे 50,43,893 परिवार लाभान्वित हुए हैं और पूरे देश में केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के रूप में 28,390.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पीएम कुसुम योजना के तहत, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, घटक -क के अंतर्गत 1986.30 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित की गई है, घटक-ख के अंतर्गत 11.68 लाख से अधिक ऑफ-

ग्रिड सिंचाई पंप लगाए गए हैं, और घटक -ग के अंतर्गत 16.70 लाख से अधिक ग्रिड-कनेक्टेड सिंचाई पंपों का सौरीकरण किया गया है।

(ख) महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित एफपीओ भी प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएम-कुसुम योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलने से डीजल पर खर्च कम हो जाता है और सिंचाई के लिए दिन के समय सौर विद्युत की विश्वसनीय उपलब्धता के साथ, कृषि उत्पादकता भी बढ़ जाती है।

(ग) उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी ने सूचना दी कि घटक-ग व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (आईपीएस) के तहत, पीएम कुसुम योजना के तहत, केंद्रीय वित्तीय सहायता और राज्य सब्सिडी के रूप में बरहपुर ब्लॉक सहित इटावा जिले के 27 किसान लाभार्थियों को कुल 1.34 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इस योजना में महिला उद्यमियों या ओबीसी महिलाओं के नेतृत्व वाले एफपीओ के लिए कोई विशेष सब्सिडी प्रावधान नहीं है।

*****